वित्तीय वर्ष 2012–13
विधि विभाग की उपलब्धियां

1. डिहरी अनुमण्डलीय न्यायालय की स्थापना

डिहरी अनुमण्डल खुले हुए काफी दिन हो गया था, पर अनुमण्डलीय न्यायालय नहीं खुला था। इसके लिए विधि विभागीय अधिसूचना सं0–2518 दिनांक 29.03.12 द्वारा 07.04.12 के प्रभाव से रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी अनुमण्डलीय न्यायालय की स्थापना किया गया है। जिसके लिए अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंसिफ तथा दो न्यायिक दण्डाधिकारी सहित कुल 4(चार) न्यायिक पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग–3 एवं वर्ग-4) कुल 39(उनचालीस) पदों का सृजन किया गया है।

2. बंदी की मुक्ति

State Remission Board की अनुशंसा पर 01.01.12 से अबतक 164 आजीवन कारावास भोग रहे कैदियों को कारा मुक्त करने का आदेश विधि विभाग द्वारा निर्गत किया गया है।

3. राज्य में 305 अधिवक्ताओं की नोटरी के रूप में नियुक्ति

राज्य की जनता को Affidavit तथा दूसरे नोटरियल कार्य में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 305 अधिवक्ताओं की नोटरीज के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी करना है।

4. सम्पर्क कार्यालय दिल्ली में अपर सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी के पद का सृजन तथा पदस्थापन

बिहार सरकार की वादों का उच्चत्तम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीकरण में अनुश्रवण हेतु अपर सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी तथा उनकी सहायता के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग–3 एवं वर्ग–4) के पदों का सृजन किया गया है तथा अपर सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी की पदस्थापना हो चुकी है जो वादों के अनुश्रवण के अलावा स्थायी सलाहकार/अपर स्थायी सलाहकारों तथा वरीय अधिवक्ताओं के बीच कार्य का वितरण, वकालतनामा निर्गत करना तथा उनके शुल्कादि के भुगतान का कार्य करेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों में भारत सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित कार्य का सुचारू रूप से संपादन करेंगे।

5. अभियोजन की स्वीकृति

01.01.12 से अबतक भ्रष्टाचार एवं गबन के कुल 41(एकतालीस) मामलों विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दिया जा चुका है, जिसमें से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कुल 23(तेईस) मामलें है।

6. शिवहर व्यवहार न्यायालय की स्थापना

शिवहर में व्यवहार न्यायालय के गठन की कार्रवाई काफी तेजी से चलायी जा रही है और आधारभूत संरचना संबंधी कार्रवाई भी लगभग पूर्ण हो चुकी है, न्यायिक पदाधिकारियों के पद का सृजन हो चुका है और निकट भविष्य में शिवहर व्यवहार न्यायालय चालू किये जाने की संभावना है।